यातायात चालान के 6,200 करोड़ रुपये की नहीं हो सकी है वसूली

एक वाहन के 100 और उससे अधिक चालान तक बकाया

आलोक मिश्र● जागरण

- हर वर्ष कम हो रहा शमन शुल्क की वसूली का प्रतिशत
- कोर्ट में 3.52 करोड़ से अधिक यातायात चालान लंबित

लखनऊ : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश हैं। केंद्र सरकार ने यातायात नियमों को सख्त कर चालान राशि में बढ़ोतरी भी की है, इसके बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है। सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है और इस पर अंकुश लगाने के लिए ही ई-चालान प्रणाली लागू की गई पर उसका भय नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में यातायात चालान के 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का शमन शुल्क वसूला नहीं जा सका है। पिछले पांच वर्षों में शमन शुल्क की वसूली का प्रतिशत भी लगातार कम हुआ है। वर्तमान में कोर्ट में 3.52 करोड़ से अधिक यातायात चालान लंबित हैं। प्रदेश में एक ही वाहन के 100 व उससे अधिक चालान तक बकाया हैं।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध ई-चालान की कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। ट्रैफिक पुलिस अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के ई-चालान करती है, जिसका भुगतान आनलाइन किए जाने की भी सुविधा है। यातायात निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ई-चालान होने के तीन दिनों के भीतर स्टेट बैंक के माध्यम से शमन शुल्क का आनलाइन भुगतान किया जा सकता है। तीन दिन बाद ई-चालान कोर्ट चला जाता है। चालान के कोर्ट पहुंचने के बाद वाहन स्वामी उसे छुड़ाने के लिए लोक अदालत की प्रतीक्षा करते हैं। यही वजह है कि कोर्ट में लंबित चालानों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। आंकड़े इसके गवाह हैं। वर्ष 2020 में 77,02,508 चालान हुए थे और इनमें 44,04,437 चालान कोर्ट में लंबित रह गए थे। वर्ष 2021 में 67,28,092 चालान में 43,93,439 चालान कोर्ट में लंबित रहे और वर्ष 2022 में 82,81,476 चालान हुए जिनमें 59,69,736 चालान कोर्ट में लंबित रहे। वर्ष 2023 में 13,26,6795 चालानों में कोर्ट में 1,03,13,872 लंबित रहे। वर्ष 2024 में 1,32,66,795 चालानों में कोर्ट में 94,10,498 चालान लंबित रहे।

वर्ष 2020 से बीती 15 मार्च तक के आंकड़े देखें तो 5,20,07,976 चालानों में 35290440 कोर्ट में लंबित हैं। ई-चालान के शमन शुल्क वसूली प्रतिशत की बात करें तो वर्ष 2020 में यह 30.76 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021 में 32.59 प्रतिशत, 2022 में 16.09 प्रतिशत और 2023 में 9.12 प्रतिशत ही रह गया। पिछले वर्ष यह प्रतिशत केवल 4.21 ही रहा और इस वर्ष अब तक लगभग 1.83 प्रतिशत ही शमन शुल्क वसूला जा सका है। एडीजी यातायात के.सत्यनारायण का कहना है कि बार-बार चालान होने के बाद भी लगातार यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को सूचीबद्ध कराया जा रहा है। परिवहन विभाग के सहयोग से ऐसे वाहनों का पंजीकरण व वाहन स्वामी का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में प्रत्येक बुधवार को पर्यटन बंद

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : वन्यजीवों को एकांत देने और वनकर्मियों को आराम देने के लिए टाइगर रिजर्व में साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था लागू कर दी गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में प्रत्येक बुधवार को पर्यटन बंद रहेगा। इस संबंध में शुक्रवार को प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमूरी का आदेश टाइगर रिजर्व प्रशासन के पास पहुंच गया। उन्होंने अन्य अभ्यारण्यों के साप्ताहिक अवकाश भी तय किए हैं।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र 15 नवंबर से 15 जून तक चलता है। इस अवधि में पर्यटक सप्ताह के सातों दिन भ्रमण करने आ सकते हैं। प्रत्येक दिन पर्यटन होने से सफारी चालकों, गाइडों को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता था, वन्यजीवों के बीच आवाजाही भी नियमित होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश तय कर दिए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पीलीभीत में बुधवार को बंदी रहेगी। इसके अलावा, रानीपुर टाइगर रिजर्व सोमवार, दुधवा नेशनल पार्क मंगलवार को बंद रहेगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की साप्ताहिक बंदी गुरुवार को होगी। किशनपुर वन्यजीव विहार बुधवार और कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार गुरुवार को बंद रहेगा।

कनिष्ठ सहायक की 29 जून, प्राविधिक सहायक की 13 जुलाई को भर्ती परीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने दो प्रमुख भर्तियों कनिष्ठ सहायक, लिपिक और प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। इन परीक्षाओं के लिए आयोग ने कुछ समय पहले ही अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया था। ऐसे अभ्यर्थी आनलाइन शुल्क जमा करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

पहली परीक्षा कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्तर-तीन के कुल 5512 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। 29 जून को होने वाली इस परीक्षा में कुल 2,43,981 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं, दूसरी परीक्षा कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 3446 पदों पर भर्ती के लिए होगी। इसमें कुल 37,845 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है। यह परीक्षा 13 जुलाई को होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए आयोग ने शुल्क निर्धारण कर दिया है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को 200 रुपये, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को 80 रुपये शुल्क देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क आनलाइन जमा किया जा सकेगा।

सालार गाजी की दरगाह के बाद लक्कड़ शाह के उर्स पर भी लगी रोक

जागरण संवाददाता, बहराइच : आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में मेले पर रोक के बाद अब लक्कड़ शाह की मजार पर लगने वाले सालाना उर्स पर भी रोक लगा दी गई है। मजार वन संरक्षित क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए वन विभाग ने अनुमति नहीं दी है। उर्स पर रोक के बाद मजार के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बीच लक्कड़ शाह की मजार बनी है। मजार किसने बनवाई और कब बनी, इसकी जानकारी वन विभाग को भी नहीं है। धीरे-धीरे यहां मेला लगने लगा। यहां सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत नेपाल से भी लोग पहुंचने लगे। हजारों की संख्या में लोग जियारत के नाम पर आते थे। प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट बी. शिवशंकर ने बताया कि वन संरक्षित क्षेत्र में लगने वाले उर्स पर इस बार रोक लगा दी गई है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान से जोड़े जाएंगे 50 लाख किसान

- 'लैब टू लैंड' नारे को साकार करने में जुटी योगी सरकार
- हर जिले में दी जा रही है खरीफ की खेती संबंधी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 के माध्यम से योगी सरकार 'लैब टू लैंड' नारे को साकार करने का प्रयास कर रही है। अभियान से 50 लाख किसानों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने के लक्ष्य का एक तिहाई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की थी और कहा था कि कृषि विज्ञानी अपनी लैब से निकलकर लैंड (खेतों) पर जाएंगे व किसानों के साथ संवाद कर कृषि की समस्याओं का हल खोजेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में 12 हजार विज्ञानी को जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ कृषि विभाग, कृषि विवि, कृषि विज्ञान केंद्रों के वेज्ञानी, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, मधुमक्खी पालन व सिंचाई विभागों के अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे। हर जिले में आयोजन होंगे और इसके लिए 225 टीमें गठित की गई है। कुल 10,125 स्थलों पर किसानों से संवाद किया जाएगा। अभियान में किसानों को खरीफ फसलों की आधुनिकतम तकनीक, प्राकृतिक खेती से जन, जमीन और जल को होने वाले लाभ के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। खरीफ की फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत बीजों के उपयोग, बीज शोधन, मिट्टी स्वास्थ्य सुधार, सहफसली खेती, ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई, खेतीबाड़ी में ड्रोन के इस्तेमाल, औद्यानिक फसलों की उपज व गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय, फसल सुरक्षा के उपायों आदि के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है।

किसानों को ढैंचा बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया है कि मृदा में जीवांश कार्बन व जैविक पदार्थ की वृद्धि और उर्वरता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 सामान्य वितरण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत 50% अनुदान पर ढैंचा बीज का वितरण किया जा रहा है। सभी जिलों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर अब तक 11,656 क्विंटल बीज की आपूर्ति कराई जा चुकी है। विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थी किसान अनुदान पर 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर सीमा तक बीज राजकीय बीज गोदाम से बीज प्राप्त कर कर सकते हैं।

राज्य में विकसित किए जाएंगे 168 योग पार्क

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: योगाभ्यास के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में 168 योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों के चयन के लिए आयुष विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। योजना के तहत मंडल मुख्यालय वाले जिलों में तीन-तीन और अन्य जिलों में दो-दो योग पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के विकास में भारत सरकार भी मदद देगी।

स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर निकायों) के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश में 1000 योग पार्क स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को जिले में योग पार्क के लिए पार्कों का चयन कर इसकी सूचना विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि योग पार्क के लिए ऐसे पार्कों का चयन किया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग योग कर सकें।

एमएसएमई टूल रूम-कोलकाता
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार सोसायटी
बॉन हुगली औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता- 700108
ई-मेल : cttc-msme@gov.in, वेबसाइट : www.msmetoolroomkolkata.com

बीसीसीएल BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड Bharat Coking Coal Limited

प्रवेश सूचना

दक्षता विकास कार्यक्रम

सीएसआर कार्यक्रम के तहत बीसीसीएल द्वारा प्रायोजित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), भारत सरकार ने सीएसआर परियोजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय, एमएसएमई टूल रूम, कोलकाता (अग्रणी टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र), को सीएनसी, कैड/कैम, वेल्डिंग एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम योग्य और इच्छुक युवाओं (लड़के और लड़कियों) के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अवधि (महीनों में)	योग्यता (मूलभूत)
1.	सहायक ऑपरेटर-सीएनसी-टर्निंग (टूल रूम)	6 महीने	10+2 पास
2.	सहायक ऑपरेटर - सीएनसी मिलिंग (टूल रूम)	6 महीने	10 पास
3.	जूनियर तकनीशियन - वेल्डिंग	6 महीने	10 पास
4.	ग्राफिक्स और वेब डिजाइनर	6 महीने	10+2 पास
5.	औद्योगिक में सर्टिफिकेट कोर्स ऑटोमेशन और रखरखाव	6 महीने	कक्षा 10+2 पास या आईटीआई योग्यता
6.	पारंपरिक में सर्टिफिकेट कोर्स मशीन संचालन	6 महीने	कक्षा 10+2 पास या आईटीआई योग्यता
7.	तकनीशियन-सीएनसी मशीनिंग	6 महीने	कक्षा 10+2 पास या आईटीआई योग्यता
8.	सीएनसी प्रोग्रामर-टूल रूम	6 महीने	डिप्लोमा
9.	फ्रंटलाइन जूनियर सुपरवाइजर (निर्माण)	6 महीने	डिप्लोमा
10.	जूनियर डिजाइनर कैड/कैम	6 महीने	डिप्लोमा

- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।

विशेष रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिष्ठित निजी संगठनों में रोजगार प्राप्त करने में शतप्रतिशत सहायता

सभी कार्यक्रम जुलाई 2025 से शुरू होंगे

इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपना पंजीकरण करें

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें: www.msmetoolroomkolkata.com या प्रशिक्षण हेल्पलाइन नं. : 93301 93304 पर संपर्क करें।

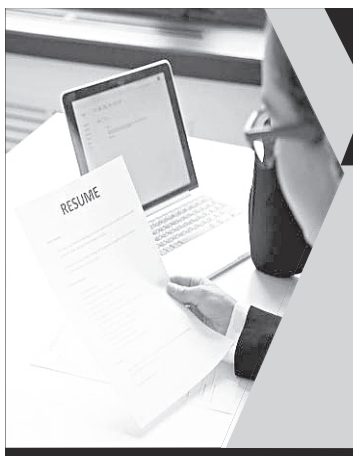

प्रगत संगणन विकास केंद्र
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

हमसे जुड़ें
हम भर्ती कर रहें हैं
प्रतिभाओं की खोज
रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए

वैज्ञानिक और तकनीकी पद

परियोजना सहयोगी (नवागत / अनुभवी)
परियोजना अभियंता (नवागत / अनुभवी)
वरिष्ठ परियोजना अभियंता
परियोजना नेतृत्वकर्ता
मॉड्यूल नेतृत्वकर्ता (न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव)
परियोजना प्रबंधक
परियोजना वितरण प्रबंधक
प्रोग्राम प्रबंधक
ज्ञान सहभागी(नॉलेज पार्टनर) (न्यूनतम 9 वर्षों का अनुभव)

योग्यता
1. बीई/बीटेक या समकक्ष डिग्री
2. विज्ञान/ कंप्यूटर अनुप्रयोग या प्रासंगिक डोमेन में स्नातकोत्तर डिग्री/एमबीए
3. एम.ई./एम.टेक या समकक्ष डिग्री
4. पीएच.डी.

गैर-तकनीकी पद

परियोजना सहायता स्टाफ / परियोजना अधिकारी (शैक्षिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम 0 - 3 वर्ष का अनुभव)

योग्यता
1. स्नातक
2. पोस्ट ग्रेजुएट
3. सीए / एलएलएम/ सीएमए / इंटर सीए
4. प्रासंगिक क्षेत्र में दो साल का पूर्णकालिक एमबीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर पेशेवर योग्यता

भारत में विभिन्न स्थलों के लिए
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 20 जून 2025
विस्तृत विज्ञापन और आवेदन करने के लिए www.cdac.in के CAREERS पृष्ठ पर जाएं।

Branding & Communication/CorpHR/C-DAC Pune 2025

ADVT.NO.CORP/JIT/03/2025 Advancing Technology for National Development CORPORATE HRD

CBC 06132/12/0001/2526

MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)
जागृति विहार, बुर्ला- 768020, जिला-संबलपुर, ओडिसा
दूरभाष (ईपीबीएक्स) : 0663-2542461 से 469, वेबसाइट : www.mahanadicoal.in

सूचना

सामानों, कार्यों एवं सेवाओं के क्रय हेतु सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी सभी निविदाएं कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in, संबंधित सहायक कंपनी (एमसीएल, www.mahanadicoal.in) सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://coalindiatenders.nic.in एवं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल https://gem.gov.in के माध्यम से भी ये क्रय उपलब्ध है। R-5257

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट
All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, Gujarat 360110
A Central Autonomous Body under PMSSY, MoH&FW
Government of India www.aiimsrajkot.edu.in

एम्स/राजकोट/प्रशासन/भर्ती/गैर-संकाय/2025-26/2847 दिनांक : 14.05.2025

रोलिंग विज्ञापन

ग्रुप 'ए' प्रतिनियुक्ति के आधार पर
एम्स राजकोट में गैर-संकाय पद पर भर्ती

एम्स राजकोट में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न ग्रुप 'ए' गैर-संकाय पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्रम.सं.	पद का नाम	वेतन स्तर (7वां सीपीसी)	पदों की सं.
1.	चिकित्सा अधीक्षक	स्तर - 14	1
2.	अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	स्तर - 13	1
3.	सहायक नियंत्रक परीक्षा	स्तर - 11	1
4.	कार्यपालक इंजीनियर (विद्युतीय)	स्तर - 11	1
5.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	स्तर - 11	1
6.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	स्तर - 11	1
7.	लेखा अधिकारी	स्तर - 10	1

विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए www.aiimsrajkot.edu.in. संस्थान की वेबसाइट देखें.

Sd/- कार्यकारी निर्देशक

लोक निर्माण विभाग, जीएनसीटीडी, दिल्ली

शुद्धिपत्र

23.05.2025 को दैनिक जागरण में प्रकाशित इस कार्यालय की रुचि की अभिव्यक्ति के अनुक्रम में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

मौजूदा	संशोधित / पढ़ें
फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज और सबवे के नीचे के क्षेत्र के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्तियाँ	फुट ओवर ब्रिज, सबवे, बड़े सड़क चौराहों और फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्तियाँ
जमा करने की तिथि: 06.06.2025 को या उससे पहले	जमा करने की तिथि: 10.06.2025 को या उससे पहले

रुचि की अभिव्यक्ति की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

कार्यकारी अभियंता
शाहदरा रोड डिवीजन (एम211),
पीडब्ल्यूडी, जीएनसीटीडी, दिल्ली-110091

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
राउरकेला इस्पात संयंत्र
राउरकेला - 769011 (ओडिशा), भारत

Great Place To Work. Certified

सूचना

कृपया ध्यान दें : राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के पूर्व कर्मचारी / मृत पूर्व कर्मचारियों के नामांकित व्यक्ति जो कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ई.एफ. बी.एस.) में नामांकित हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के पूर्व कर्मचारी या मृत पूर्व कर्मचारियों के नामांकित व्यक्ति, जो कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत नामांकित हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति की आनुमानिक तारिख बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक ई.एफ. बी.एस. योजना के अंतर्गत जमा की गई अपनी भविष्य निधि (पी.एफ.) और ग्रेच्युटी राशि का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने जानकारी की पुष्टि करें।

ऐसे व्यक्तियों की सूची संपर्क पोर्टल https://sampark.sailrsp.co.in पर उपलब्ध है।

यदि इस सूची में आपका नाम है, तो आपको आगे की सहायता के लिए आर.एस.पी. के ई.आर.एण्ड सी. अनुभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

➢ संपर्क नंबर : 0661-244-8506 (कार्यालय समय के दौरान)

जिन्होंने पहले ही दावा कर लिया है , वे कृपया इस सूचना को नज़रंदाज़ करें।

पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली आवास परियोजना

लर्नेड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
द्वारा निष्पादित

ई-नीलामी के माध्यम से इन्वेंट्री बल्क सेल

एन बी सी सी NBCC नवरत्न सीपीएसई

ASPIRE

ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख 02.06.2025

आपके परिवार के लिए आदर्श घर

3 और 4 बीएचके स्पेशियस लक्जरी अपार्टमेंट्स

- आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रोजेक्ट
- गौर सिटी मॉल, प्रसिद्ध अस्पतालों और स्कूलों के नजदीक
- इंडिया गेट, आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन: 30 मिनट

ई-नीलामी दिनांक 03.06.2025 को आयोजित की जाएगी

कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए इस क्यूआर को स्कैन करें।

अधिक जानकारी के लिए,
कृपया हमारी वेबसाइट देखें:
www.nbccindia.in | www.receiveramrapali.in
या कॉल करें: 9772907414

कृपया लोकेशन के लिए क्यूआर स्कैन करें।